कृषि 24/7

संदर्भ: कृषि 24/7, कृषि समाचारों की स्वचालित निगरानी और विश्लेषण के लिए एआई-संचालित समाधान पेश करता है।

- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) ने, AI-संचालित कृषि समाचार निगरानी और विश्लेषण समाधान कृषि 24/7 विकसित करने के लिए वाधवानी AI और Google.org के साथ सहयोग किया है।
- कृषि 24/7 प्रासंगिक समाचारों की पहचान करने, अलर्ट उत्पन्न करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
- यह टूल बहुभाषी कृषि समाचार लेखों को स्कैन कर उनका अंग्रेजी में अनुवाद करता है।
- यह कृषि सम्बन्धी सभी मुख्य जानकारी एकत्र करता है, जिसमें शीर्षक, फसल विवरण, घटना प्रकार, तिथियां, स्थान, गंभीरता, सारांश और स्रोत लिंक शामिल हैं।
- यह प्रणाली ऑनलाइन कृषि समाचारों की लगभग वास्तविक समय पर निगरानी प्रदान करती है।
- कृषि 24/7 कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है।
- यह पहल विकसित हो रहे सूचना परिदृश्यों में निरंतर सुधार और अनुकूलन क्षमता पर केंद्रित है।
- इस सहयोग का उद्देश्य प्रभावी उपकरणों के माध्यम से कृषि में डेटा-संचालित निर्णयों में सुधार करना है।
- **कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
  - सितंबर 2021 में शुरू की गई डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम) पहल, क्लाउड कंप्यूटिंग, पृथ्वी अवलोकन, रिमोट सेंसिंग, डेटा और एआई/एमएल मॉडल का उपयोग करके कृषि-तकनीक स्टार्टअप का समर्थन करती है।
  - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; कृषि के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों का एक व्यापक सेट 'एग्रीस्टैक' विकसित कर रहा है।
  - यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म (यूएफएसपी) देशभर में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी आईटी प्रणालियों के बीच निर्बाध अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, एप्लिकेशन और टूल को एकीकृत करता है।
  - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों और कम कृषि बिजली उपलब्धता वाले क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण का विस्तार करना है।
  - इस संबंध में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी-ए); एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2010-11 में 7 राज्यों में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य आईसीटी के उपयोग के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध कराकर भारत में तेजी से विकास को बढ़ावा देना है।
  - एनईजीपी-ए के साथ-साथ, किसान कॉल सेंटर, किसान सुविधा ऐप, कृषि बाजार ऐप, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) पोर्टल सहित कई अन्य डिजिटल पहल लागू की गई हैं। ये पहल किसानों के लिए कृषि सेवाओं और सूचना पहुंच को बेहतर बनाने में योगदान करती हैं।

ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक (एआईईएससी)

संदर्भ: भारत सरकार के शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता कैबिनेट मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने गांधीनगर में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद बैठक (एआईईएससी) की सह-अध्यक्षता की।

- **एआईईएससी बैठक और अवलोकन:**
  - श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद (एआईईएससी) बैठक की सह-अध्यक्षता की।
  - AIESC भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा और कौशल विकास साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है।
  - यह अंतर्राष्ट्रीयकरण, दो-तरफा गतिशीलता और शिक्षा और कौशल में सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **प्रमुख पहल और समझौते:**
  - **ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय HEI के बीच समझौता ज्ञापन:** कृषि, जल प्रबंधन, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य देखभाल, AI, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के बीच पांच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।
  - **इनोवेटिव रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ (आईआरयू) कंसोर्टियम कैंपस**: सात ऑस्ट्रेलियाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में देश में शिक्षण डिग्री का पता लगाना और भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना है।
  - **डीकिन (Deakin) विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी):** डीकिन विश्वविद्यालय और एनएसडीसी ने भारत में कौशल की कमी को दूर करने के लिए 'ग्लोबल जॉब रेडीनेस प्रोग्राम' विकसित किया, जिससे 15 मिलियन भारतीयों को कौशल प्रदान किया गया।
  - **डीकिन यूनिवर्सिटी और आईआईटी गांधीनगर:** डीकिन यूनिवर्सिटी, गिफ्ट सिटी में अपने परिसर के साथ, विज्ञान, नवाचार, संकाय विनिमय और संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रमों पर आईआईटी गांधीनगर के साथ सहयोग करती है।
  - **मोनाश विश्वविद्यालय और आईआईटी हैदराबाद**: यह समझौता ज्ञापन महत्वपूर्ण खनिजों और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग पर केंद्रित है।
  - **मोनाश विश्वविद्यालय और खनन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईएम):** यह समझौता ज्ञापन भारत में खनन और खनिज विकास क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और नवाचार सहयोग का समर्थन करता है, जो जलवायु परिवर्तन शमन, दक्षता और महत्वपूर्ण खनिजों पर जोर देता है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी)

संदर्भ: हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई गई।

- **स्थापना:** सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है।
- **सदस्य:** सीआईसी में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त शामिल होते हैं।

- **नियुक्ति:** राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश के आधार पर उनकी नियुक्ति करते हैं। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
- **क्षेत्राधिकार:** आयोग के अधिकार क्षेत्र में सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं।
- **कार्यकाल:** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कार्यकाल तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक सेवा करते हैं। इन्हें पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है।
- **केंद्रीय सूचना आयोग की भूमिका:**
  - केवल उचित आधार (suo-moto power) पर मामलों की जांच का आदेश देना।
  - किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
  - निम्नलिखित मामलों में व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त कर उनकी जांच करना:
    - यदि निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना के लिए उनके अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया जाता है।
    - यदि प्रदान की गई जानकारी को अपूर्ण, गलत या भ्रामक माना जाएगा।
    - यदि जानकारी सुरक्षित करने से संबंधित कोई भी मामला हो।
    - किसी अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थता हो।
    - अनुचित शुल्क वसूलने पर विचार किया जा रहा हो।
      - आयोग के पास सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में किसी भी रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार है। ऐसे सभी रिकॉर्ड परीक्षा के दौरान आयोग को उपलब्ध कराए जाने चाहिए और इस सन्दर्भ में कुछ भी रोका नहीं जा सकता।
  - पूछताछ के दौरान, सीआईसी के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती हैं, जिनमें निम्नलिखित शक्तियां भी शामिल है:
    - व्यक्तियों को शपथ के तहत मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेज़ या वस्तुएँ प्रस्तुत करने के लिए बुलाना और मजबूर करना।
    - दस्तावेज़ों की खोज और निरीक्षण करना।
    - शपथ पत्र पर साक्ष्य स्वीकार करना।
    - किसी कार्यालय या न्यायालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड या प्रतियों का अनुरोध करना।
    - दस्तावेजों या गवाहों की जांच के लिए समन जारी करना।
    - किसी अन्य मामले को संबोधित करना जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
  - सीआईसी अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट बाद में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है।
- **हालिया संशोधन**
  - आरटीआई अधिनियम, 2005 ने शुरू में केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और सूचना आयुक्तों (आईसी) के कार्यकाल, सेवा की शर्तों और वेतन को निर्दिष्ट किया था।
  - आरटीआई (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने इन प्रावधानों को हटा दिया, जिससे केंद्र सरकार को नियमों के माध्यम से कार्यकाल और वेतन निर्धारित करने का अधिकार मिल गया।
  - संशोधन से पहले, सीआईसी और आईसी का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित था।
  - वर्तमान संशोधन ने पिछली सरकारी सेवा से पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के कारण वेतन में कटौती के प्रावधानों को समाप्त कर दिया।
  - इसने केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सीआईसी और आईसी के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की।

खाद्य एवं कृषि रिपोर्ट-2023

संदर्भ: हाल ही में जारी वर्तमान खाद्य एवं कृषि रिपोर्ट-2023; में कहा गया है कि 7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की वार्षिक (छिपी हुई) लागत अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, वसा और शर्करा से भरपूर अस्वास्थ्यकर आहार के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

- **अस्वास्थ्यकर आहार की छिपी हुई लागत:**
  - अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, वसा और शर्करा सहित अस्वास्थ्यकर आहार के परिणामस्वरूप वैश्विक नुकसान वार्षिक तौर पर 7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होता है।
  - इन आहारों से मोटापा, गैर-संचारी रोग और श्रम उत्पादकता में कमी आती है।
  - इसका प्रभाव उच्च और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में अधिक स्पष्ट है।
- **कृषि खाद्य प्रणालियों की लागत:**
  - वर्तमान कृषि खाद्य प्रणालियाँ वार्षिक 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बराबर छिपी हुई लागत लगाती हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है।
  - खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अध्ययन में 154 देशों का विश्लेषण किया गया।
  - ये खर्च अन्य कारकों के अलावा अस्वास्थ्यकर आहार के प्रभाव से संबंधित हैं।
- **ग्रामीण और शहरी उपभोग पैटर्न:**
  - शहरीकरण, जीवनशैली में बदलाव और रोजगार प्रोफाइल से प्रभावित होकर, उप-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ रही है।
  - वर्तमान शोध इस अवधारणा को चुनौती देता है, कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदारी के अलग-अलग पैटर्न होते हैं; साथ ही ये प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का प्रसार दोनों संदर्भों में व्यापक है।
  - उच्च-खाद्य-बजट वाले देशों में कुल भोजन खपत का लगभग 29% प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, जबकि कम-खाद्य-बजट वाले देशों में यह खपत मात्र 25% है।
- **वैश्विक खाद्य असुरक्षा:**
  - वैश्विक स्तर पर मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा लगातार दूसरे वर्ष 2022 में अपरिवर्तित रही।

- वर्ष 2022 में, वैश्विक आबादी के लगभग 29.6% (2.4 बिलियन लोगों) ने मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया।
- दुनिया की 11.3% आबादी (लगभग 900 मिलियन लोग) को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा।

➢ **भूख और अल्पपोषण:**

- अनुमान है कि वर्ष 2022 में 691-783 मिलियन लोगों ने भूख और अल्पपोषण का अनुभव किया।
- वैश्विक महामारी से पहले, वर्ष 2019 की तुलना में यह 122 मिलियन लोगों की वृद्धि है।
- रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 में लगभग 600 मिलियन लोग लंबे समय तक अल्पपोषित रहेंगे।

➢ **दक्षिण एशियाई देश और भारत:**

- दक्षिण एशियाई देशों में, भारत में अल्पपोषण का तीसरा सबसे बड़ा प्रसार था, जहां 233.9 मिलियन लोग इसका अनुभव कर रहे थे।
- भारत में कुपोषित लोगों का प्रतिशत 2004-06 में 21.4% से घटकर 2020-22 में 16.6% हो गया।

➢ **आय स्तर के अनुसार छिपी हुई लागत:**

- कम आय वाले देश कृषि खाद्य प्रणालियों से छिपी लागत का सबसे बड़ा बोझ उठाते हैं, जो उनके सकल घरेलू उत्पाद का 25% से अधिक है।
- मध्य-आय वाले देशों को 12% से कम और उच्च-आय वाले देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 8% से कम छिपी लागत का सामना करना पड़ता है।

➢ **सिफ़ारिशें:**

- यह रिपोर्ट कृषि खाद्य प्रणालियों की वास्तविक लागतों के अधिक नियमित और विस्तृत विश्लेषण का सुझाव देती है।
- यह सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा वास्तविक लागत लेखांकन और शमन कार्यों की वकालत करता है।
- सही लागत लेखांकन जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता और खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने और तदनुसार कृषि खाद्य प्रणालियों को बदलने में यह रिपोर्ट मदद कर सकता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

बांदीपुर टाइगर रिजर्व

हाल ही में, सोमवार को कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मोलियूर रेंज में एक बाघ ने लगभग 30 साल के एक किसान को मार डाला।

बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में:

- बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना 1930 के दशक में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में की गई थी और बाद में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में इसे बाघ रिजर्व बना दिया गया।
- यह कर्नाटक के दो निकटवर्ती जिलों, मैसूर और चामराजनगर में स्थित है।
- बांदीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर पश्चिम में नागरहोल टाइगर रिजर्व (तमिलनाडु), दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (तमिलनाडु) और दक्षिण पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल) से घिरा हुआ है, इसके उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी है।
- **वनस्पति:** रिजर्व में शीशम, भारतीय कीनो पेड़, चंदन, भारतीय लॉरेल, क्लंपिंग बांस और विशाल क्लंपिंग बांस सहित विविध वनस्पतियां शामिल हैं।
- **जीव-जंतु:** बांदीपुर टाइगर रिजर्व दक्षिण एशिया में जंगली एशियाई हाथियों, बंगाल टाइगर, गौर (भारतीय बाइसन), स्लॉथ भालू, गोल्डन जैकॉल, ढोल (भारतीय जंगली कुत्ता), चार सींग वाले मृग आदि का आश्रय स्थल है।

जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

हाल ही में, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (TYEP) में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक युवा प्रतिनिधिमंडल ने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

के बारे में:

- नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) वर्ष 2006 से जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम (TYEP) का आयोजन कर रहा है।
- ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वामपंथी उग्रवाद विभाग (LWE) के सहयोग से किया जाता है, जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय युवाओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना है।
- इसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं को भारत के भीतर विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित कराकर "विविधता में एकता" की अवधारणा को बढ़ावा देना है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, नेहरू युवा केंद्र संगठन देश भर में 26 आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति

हाल ही में, भारत कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) द्वारा देश की पहली लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बारे में:

- भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) सुरक्षा उद्देश्यों और रणनीतियों को रेखांकित करने वाला पहला व्यापक दस्तावेज़ है।
- भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को समय के साथ पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने, कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- यह सैन्य, रक्षा और सुरक्षा सुधारों के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करेगा , जो राष्ट्रीय सुरक्षा, खतरों और रणनीतियों पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

- इसमें वित्तीय, आर्थिक, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, सूचना युद्ध, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमजोरियां, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे और पर्यावरण संबंधी चिंताओं सहित समकालीन चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस जैसे विकसित देशों की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियाँ हैं।
- पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए 2022-2026 के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया था।

एलिसियस हिमालय

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की एक गुफा में एलिसियस हिमालय नामक घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की गई।

एलिसियस हिमालय (Alycaeus Himalayae) के बारे में:

- एलिकेअस हिमालय एलीकेअस वंश से संबंधित है, जो छोटे भूमि घोंघों के लिए जाना जाता है।
- एलिसियस जीनस पहले भारत में नहीं पाया गया था और आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया तक ही सीमित है।
- यह नई प्रजाति अपने पीले, शंक्वाकार खोल के कारण हिमालयी एलिकाइड प्रजातियों में अद्वितीय है।
- आस-पास पाया जाने वाला सबसे समान शंख शान स्टेट्स, म्यांमार से प्राप्त स्टोमाकोस्मिथिस स्प्रेटी है।
- ऑपरकुलम के बाहरी तरफ एक विशिष्ट तुरही जैसे प्रक्षेपण के कारण यह अन्य सभी एलिसियस प्रजातियों से भिन्न है।
- एलिसियस हिमालय हिमालय क्षेत्र में रहने वाली एकमात्र एलिसियस प्रजाति है।
- अन्य ज्ञात एलिसियस प्रजातियाँ मुख्य रूप से लाओस, वियतनाम, दक्षिणी थाईलैंड और प्रायद्वीपीय मलेशिया जैसे देशों से बताई गई हैं।

लिसियोनोटस नामचूमी

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) के वैज्ञानिकों ने हाल ही में "लिसियोनोटस नामचूमी" नामक एपिफाइटिक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है।

लिसियोनोटस नामचूमी (Lysionotus namchoomii) के बारे में:

- जीनस लिसिओनोटस हिमालय, जापान और इंडो-चीन का मूल निवासी है।
- इस नई प्रजाति की विशेषता इसकी मोटी पत्तियां और आकर्षक बैंगनी फूल हैं।
- इसका नाम अरुणाचल प्रदेश के खप्ति समुदाय (Khapti community)के समाज सुधारक स्वर्गीय चाऊ फुंक्यु नोमचून के सम्मान में रखा गया है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई):

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में हुई थी।
- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत शीर्ष अनुसंधान संगठन के रूप में कार्य करता है।
- यह भारत के जंगली पौधों के संसाधनों पर वर्गीकरण अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार है।

रहस्यमय ब्लॉब

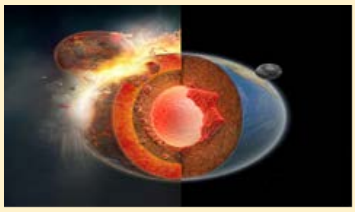

हाल ही में, भूकंप विज्ञानियों ने 1970 के दशक से अफ्रीका और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के नीचे पृथ्वी के आवरण में महाद्वीप के आकार की दो रहस्यमय ब्लॉब की पहचान की है।

रहस्यमय ब्लॉब (Mysterious Blobs) के बारे में:

- रहस्यमय ब्लॉब, जिन्हें बड़े निम्न-वेग प्रांत (एलएलवीपी) के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के आवरण के भीतर, सतह से लगभग 1,000 मील नीचे, गहराई में खोजी गई हैं।
- इनमें से प्रत्येक एलएलवीपी एक महाद्वीप जितना बड़ा है और माउंट एवरेस्ट से लगभग 100 गुना ऊंचा है।
- ये रहस्यमय ब्लॉब पृथ्वी की सतह से लगभग 2,900 किलोमीटर नीचे स्थित हैं, जो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 2% बनाती हैं।
- इनमें से प्रत्येक बूँद का द्रव्यमान पूरे चंद्रमा के द्रव्यमान से दोगुना होने का अनुमान है।
- बूँदों का बढ़ा हुआ घनत्व उनमें उच्च लौह सामग्री के कारण होता है।
- भविष्य के चंद्र मिशन उनकी समस्थानिक संरचना का परीक्षण करने में मदद कर सकते हैं, जो चंद्र मेंटल चट्टानों के समान होने की उम्मीद है।

डीपफेक टेक्नोलॉजी

हाल ही में, एक ब्रिटिश भारतीय महिला के मूल वीडियो पर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का चेहरा लगाकर बनाया गया एक डीपफेक वीडियो विवाद का विषय बन गया है।

डीपफेक टेक्नोलॉजी के बारे में:

- डीपफेक टेक्नोलॉजी में शक्तिशाली कंप्यूटर और डीप लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके वीडियो, छवियों और ऑडियो में हेरफेर शामिल है।
- इसका उपयोग फर्जी समाचार, वित्तीय धोखाधड़ी और विभिन्न भ्रामक गतिविधियों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसमें घोटाले, धोखाधड़ी, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफ़ी, चुनाव हेरफेर, सोशल इंजीनियरिंग, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी शामिल हैं।
- "डीपफेक" शब्द की उत्पत्ति 2017 में हुई जब एक गुमनाम रेडिट (Reddit) उपयोगकर्ता ने खुद को "डीपफेक" के रूप में पहचाना और हेरफेर किए गए वीडियो बनाने और साझा करने के लिए गूगल की ओपन-सोर्स डीप-लर्निंग तकनीक का उपयोग किया।
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों बराक ओबामा , डोनाल्ड ट्रम्प और भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित उल्लेखनीय हस्तियों का प्रतिरूपण करने के लिए डीपफेक तकनीक का उपयोग किया गया है।

अमेरिका ने डीपफेक तकनीक को संबोधित करने में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) की सहायता के लिए डीपफेक टास्क फोर्स अधिनियम पेश किया।

समाचारों में स्थान

सिएटल

हाल ही में, भारत ने सात साल की योजना के बाद सिएटल में अपना छठा वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है।

भौगोलिक अवस्थिति:

- सिएटल संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह शहर है। यह वाशिंगटन राज्य और प्रशांत नॉर्थवेस्ट दोनों में सबसे बड़ा शहर है।

भौगोलिक स्थिति:

- सिएटल पश्चिम में पुगेट साउंड (प्रशांत महासागर की एक शाखा) और पूर्व में वाशिंगटन झील के बीच एक स्थलडमरूमध्य पर स्थित है।
- पैसिफ़िक रिंग ऑफ़ फायर में शहर का स्थान इसे भूकंप के प्रति संवेदनशील बनाता है, यहाँ एक प्रमुख भूकंप क्षेत्र है।

महत्व: सिएटल माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॅन, बोइंग और अन्य सहित प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है।

दूतावास बनाम वाणिज्य दूतावास:

- दूतावास एक देश की सरकार का दूसरे देश में प्रतिनिधित्व करता है और आमतौर पर मेजबान देश की राजधानी में स्थित होता है, जिसका प्रमुख राजदूत होता है।
- वाणिज्य दूतावास मेजबान देश के प्रमुख शहरों में स्थित छोटे कार्यालय हैं, जो विदेश में रहने वाले या यात्रा करने वाले नागरिकों को कांसुलर सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे वीजा और पासपोर्ट जारी करना और आपात स्थिति और कानूनी सहायता के दौरान सहायता प्रदान करना।

POINTS TO PONDER

- 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2023' का मेजबान, कौन सा शहर है? - **नई दिल्ली**
- किस संस्था ने '2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट' जारी की? - **यूएनईपी**
- किस मंत्रालय ने जल दिवाली अभियान शुरू किया है? - **आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय**
- 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? - **गोवा**
- 'स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज' किस संस्था द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है? - **डब्ल्यूएमओ**